उत्तराखण्ड शासन राज्य सम्पत्ति विभाग संख्या– a 6 / xxxii / 2007, देहरादूनः दिनांक 66/7/2007

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक (संविलियन) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 1— संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः—

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २००७ है,

2- नियम 6 के उप नियम (5) तथा उप नियम (8) का संशोधन-

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 6 के उपनियम (5) व (8) के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रूब दिये जायेंगे ; अर्थात

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम

स्तम्भ–2 एतदुद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6(5) स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों के वाहन चालकों को राज्य सम्पत्ति विभाग में संविलियन के समय उनके जी०पी०एफ० में जमा नियोक्ता का अंश ब्याज सहित उनके नये भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा, जिसके लिए उन्हें सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनना पड़ेगा और नया भविष्य निधि खाता आवंटित किया जायेगा।

न 6(5) स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों के वाहन चालकों य को राज्य सम्पत्ति विभाग में संवितियन के समय उनके ज सी०पी०एफ० में जमा नियोक्ता का अंश ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जायेगा। संवितियन के बाद जी०पी०एफ० हेतु नया भविष्य निधि खाता आवंटित किया जायेगा; परन्तु यह कि 01 अक्टूबर, 2005 अथवा उनके

बाद संविलियित कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण जी०पी०एफ० में अंशदान करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

6(8) निगमों / संस्थाओं के इन वाहन चालकों की पूर्व सेवा, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के लिये गणना में लिया जायेगा तथा पूर्व की सेवा में अर्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश को वर्तमान सेवा में गणना में लिया जायेगा।

6(8) केंवल उन निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में की गई पूर्व की सेवाओं को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के लिये नई सेवा में जोड़ा जायेगा, जिनमें पूर्व से पेंशन, ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य हो तथा पूर्व सेवा के अन्य लाभ वर्तमान सेवा में अनुमन्य नहीं होंगे, परन्तु यह ि अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश संविलियन के बाद की देयता के अनुरूप होगा और पूर्व की सेवा के अवकाश लेखे के शेष अवकाश को वर्तमान सेवा में नहीं जोड़ा जायेगा;

परन्तु यह और कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद संविलियन कर्मी नई अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण कार्मिकों की पूर्व की सेवा की गणना पेंशनरी व अन्य लाभ हेतु वर्तमान सेवा में नहीं की जायेगी।

> (उत्पल कुमार सिंह) सचिव।

संख्या- 9 6 / xxxii / 2007, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
- 3- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, लखनऊ।
- 4- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
- 5— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सिचव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 7- निजी सचिव, मा०मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
- 8- समस्त निजी सचिव, मा0मंत्रीगण, उत्तराखण्ड ।
- 9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/ उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
- 10- मुख्य व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
- 11— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणाजय, लिंथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त' नियमावली की 200 प्रतियाँ साधारण गजट में प्रकाशित कराकर राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12- वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- प्रमुख लेखाकार/मुख्य लेखाकार, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 14- वित्त अनुभाग-7/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन्।
- 15- निदेशक, एन० आई० सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय/गार्ड फाइल।

आज्ञा से (केoएसo बिष्ट) उप सचिव। In pursuance of provisions of article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the English translation of the following notification No-....44.......... dated. 06/102/2000 general information.

Government of Uttarakhand State Estate Department N0-96/XXXII/2007 Deharadun: Dated 66/07, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provisions to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amending the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002:-

The Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (First Amendment) Rules, 2007.

1-Short title and commencement

- These rules may be called the Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (First Amendment)
 /Rules,2007.
 - (2) They shall come into force at once.

2-Substitution of sub-rule (5) and (8) of rule 6

In the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002, the following sub-rule (5) and sub-rule (8) of rule 6 as set out in column 1 shall be substituted by the following sub-rule as set out in column 2, namely:

Column -1	Column -2
(Existing rule)	The control of the co
6 (5) The employers contribution along with the interest towards the GPF accumulations of the drivers of Autonomous Bodies/ Corporations shall be credited of their new GPF account at the time of their absorption in the State Estate Department, for which they will have to become member of General Provident Fund and a new Provident Fund account shall be allotted.	6(5) The employers contribution along with the interest towards the CPF accumulations of the Auto-

allotted.

6 (8) The past service of these drivers of the Corporations/Bodies shall be counted for the purpose of pension, gratuity etc. and the earned leave/medical leave of the past service shall be taken into account in the present service. contributory pension scheme, shall not be authorized to contribute towards GPF on or after 01-10-2005.

6 (8) The past service only in those Autonomous Bodies/Corporations etc shall be added for the purpose of pension, gratuity etc. Where in pension, gratuity facilities were already admissible and other benefits of the past service shall not be admissible in the present service;

Provided that the earned leave and medical leave shall be in accordance with the liability after absorption and the balance of leave credited to the leave account during past service shall not be added in the present service. Provided further that the past service of the absorbed employees being covered under the new contributory pension scheme shall not be counted for the purpose of pensionary and other benefits in the present service on or after 01.10.2005.

DLe

(Utpal Kumar Singh) Secretary